

तौर पर नियुक्ति की गई है। शिवसेना नेता के तौर पर रामदास कदम और आनंदराओ अडसूल को नियुक्त किया गया। शिवसेना के उप नेता के तौर पर यशवंत यादव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोखे, तानाजी सावंत, विनय नाहटा, शिवाजीराव पाटिल को चना गया है।

तिजरा शीतला गुलाबो माता के मंदिर में नीलकंठ महादेव मंदिर की भूमि पूजन किया गया जिसमें आज सावन के सोमवार पर भूमि पूजन कर बेदी की बनाने की तैयारी शुरू की गई प्रदीप कुमार जैन डब्ल्यू पंडित सुरलाल शर्मा मातादीन जागिड़ महंत जसू महाराज सुनील अग्रवाल गुप्ता शर्मा कैलाश चंद गुप्ता लक्ष्मीकांत गुप्ता (लुटेरा) आदि लोग उत्सवधर हे प्राण प्रतिष्ठ 27 तारीख को शिवरात्रि पर की जाएगी जिसमें नीलकंठ महादेव की मूर्ति एवं रात्रि जागरण और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा





दखल



राजनेताओं और दलों ने डॉ भीमराव अंबेडकर और कथित दलित उत्थान की राजनीति को अपने राजनीतिक हितों का साधन और साध्य बना लेने से ज्यादा कुछ नहीं समझा। किंतु अब यह मिथक टूटने को आतुर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एक जातीय कुचक्र के टूटने भर से अन्य राजनीतिक दलों का जातिगत कुचक्र भी टूटेगा, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। गोया, गठबंधन के कुचक्र बने रहेंगे।

राज-विचार

बांग्लादेश में अब सुरक्षित नहीं हिंदू

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नई नहीं है। इस तरह की वारदात खास मकसद के लिए की जा रही है। बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। ये हिंदू परिवार पलायन कर जाते हैं और जमीन पर कट्टरपंथी कब्जा कर लेते हैं।



बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में नरैल नामक जगह पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते बवाल हो गया और हिंदू समुदाय के घरों व मंदिर में तोड़ फोड़ की गई। इसके विरोध में देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिक हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांग की है कि क्या अवांछित हमले की स्थिति को रोकने में लापरवाही हुई और क्या पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में उचित भूमिका निभाई। यह टिप्पणी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों के बाद आई है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लाम को बदनाम करने की अफवाह है। यह सब तब हुआ जब नरैल स्थित सहपारा इलाके में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई।

बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें कोई नई नहीं हैं लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि हिंसा की घटनाएं अब तक एक सीमित इलाकों में होती आई थीं लेकिन अब बड़े इलाकों तक इसकी आंच पहुंच गई है। जमात-ए-इस्लामी, हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठनों का प्रभाव पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में तेजी से बढ़ा है और सेकुलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ ये संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से फैसले बदलवाने में भी सफल रहे हैं। बांग्लादेश के अलग-अलग इलाकों में प्रभाव बढ़ रहा है तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश से अब तक लगभग 2.4 करोड़ हिंदू पलायन कर चुके हैं। वर्ष 1964 से 2013 के बीच रोजाना लगभग 600 से ज्यादा हिंदू देश छोड़कर गए। यह क्रम अब भी जारी है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले 30 साल में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म होने के साथ ही हिंदू समुदाय के साथ मार-पीट शुरू हो गई थी।

बांग्लादेश के जन्म होने के बाद 1974 में जनगणना हुई थी। इसके मुताबिक देश में 1974 में 13.5 फीसदी हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2011 में देश में महज 8.5 प्रतिशत हिंदू ही रह गए थे। 2011 से 2021 तक इसमें करीब तीन फीसदी की और गिरावट आ चुकी है। आलम यह है कि हिंदुओं की संख्या साल-दर-साल घटती जा रही है। अब तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करना, हिंदुओं के घर जलाना, बच्चों और लड़कियों का अपहरण, दुष्कर्म जैसी वारदात यहां आम हो गई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। दरअसल, यहां के हिंसा के पैटर्न में देखा गया है कि बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। घर जलने से ये हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर होते हैं और जब वे पलायन कर जाते हैं तो उनकी जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं।

प्रकृति का अधिकाधिक दोहन करने की नीतियों और मानसिकता ने समूची मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां हम सबको प्रकृति और मनुष्य की आत्मीयता के समीकरण पुनः प्रबल करने होंगे। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर बताती है कि दुनिया ने अगर अब भी होश नहीं संभाला, तो प्रकृति कहर बरपाने पर آمदादा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में हलचल मची है। मानो प्रकृति अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से अकुलाने लगी है। मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट बता रही है कि देश में पिछले साल मौसम संबंधी आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में असामान्य मौसमी घटनाओं के कारण जो आपदाएं आईं, उनमें दो हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए। अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो हर साल का सिलसिला है।

पर इन घटनाओं को प्राकृतिक कारण मान कर भुलाया दिया जाता रहा है। मान कर चला जाता है कि ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ भी आएगी, भूस्खलन भी होगा, तेज गर्मी पड़ेगी और पानी नहीं बरसेगा तो सूखा भी पड़ेगा। बमौसम की बारिश दूसरी तरह के संकट खड़े करेगी। मगर आज जब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और वैज्ञानिक साधन-उपकरण हमारे पास हैं, मौसम की भविष्यवाणियां हमें खतरों से आगाह करती रहती हैं तो फिर हम क्यों नहीं सचेत होते? प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों, आपदाओं को जन्म देने वाली मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं विचार करते? हाल में मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट ने एक बार फिर उन कारणों को सामने रखा है, जिनकी वजह से हमें प्रकृति का कोपभाजन बनना पड़ता है।

रिपोर्ट बता रही है कि गुजरात साल यानी 2021 पिछले 121 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। इससे भी ज्यादा चौकाने वाली बात यह कि 120 साल में जो सबसे ज्यादा 11 गर्म साल रहे, वे 2007 से 2021 के बीच रहे। जाहिर है, भारतीय उपमहाद्वीप के वातावरण में गर्मी बढ़ी है। यह आने वाले समय में बड़े खतरे का संकेत है। इसलिए हमें अभी से ऐसा करना होगा जिससे इस सदी के अंत तक तापमान में वृद्धि को रोक जा सके। वरना प्राकृतिक आपदाएं और विकराल रूप धारण कर कहर बरपाएंगी। हालांकि धरती का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। सारे देश इसकी मार झेल रहे हैं। समुद्रों पर इसका असर दिख रहा है, धरती के बर्फीले हिस्सों यानी ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की दर बढ़ रही है, और इससे गंभीर प्राकृतिक असंतुलन बनता जा



पर्यावरण में एअरोसाल की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी के जलचक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। एअरोसाल गैस के साथ ठोस कणों या बूंदों के मिश्रित होने की स्थिति को कहते हैं और इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण मानसून का व्यवहार भी अनियमित हो गया है। देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है तो कहीं आज भी लोगों को बारिश होने का इंतजार है।

रहा है। पिछले साल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में प्राकृतिक आपदाओं ने अपना शैद रूप दिखाया। चाहे दुनिया के जंगलों में आग की घटनाएं हों, या फिर यूरोपीय देशों में आई बाढ़, सबका कारण बढ़ता वैश्विक तापमान ही है। अब तक के सभी जलवायु सम्मेलनों में सबसे बड़ी चिंता यही उभर कर आई है कि बढ़ते वैश्विक तापमान को कैसे रोका जाए। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए तमाम संधियां हुईं, पर कोई ठोस नीतीजा आज दिखने में आया नहीं।

हैरानी की बात यह है कि जलवायु संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए भारत में ही अपने स्तर पर हमें जो कदम उठाने चाहिए, उस काम में भी हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बारिश, बाढ़, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, सूखा आदि विषम जलवायु घटनाओं में हर साल जन-धन की भारी हानि होती है। भारत विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों वाला देश है। इसलिए हर

राज्य की आपदाओं की प्रकृति भी अलग-अलग होती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में वनाग्नि और बादल फटने जैसी घटनाएं कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। दरअसल हमें विकास संबंधी नीतियों को पर्यावरण रक्षा के अनुकूल बनाने पर जोर देना होगा। तभी जलवायु संकट से निकलने का रास्ता मिलेगा। विकास के नाम पर हमने जिस जीवन शैली को अपनाया है, उसके चलते वातावरण में विषैली गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। पराबैगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत कमजोर पड़ने की चिंता जानकारों को लगातार परेशान कर रही है। दूसरी तरफ पर्यावरण में एअरोसाल की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी के जलचक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

एअरोसाल गैस के साथ ठोस कणों या बूंदों के मिश्रित होने की स्थिति को कहते हैं और इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण मानसून का व्यवहार भी

जनगणना की बात पुरजोरी से उठाई जा रही है, जिससे संख्याबल के आधार पर जातिगत आरक्षण व्यवस्था सरकारी नौकरियों के साथ विधायिका में भी की जा सके। सतीश मिश्रा के बसपा में आने के बाद सामाजिक अभियांत्रिकी का बेमेल तड़के का सिलसिला तो शुरू हुआ ही, जिन लोगों को माया मनुवादी कहकर ललकारा करती थीं, उन्हीं मनुवादियों के कर्मकांड बसपा के मंचों पर सत्ता प्राप्ति के लिए अनिवार्य अनुष्ठान बन गए। सभाओं में हवन कुंड बनाए जाने लगे और मंत्रों के उच्चारण के साथ परशुराम के सोने-चांदी के फरसे ब्राह्मणत्व के प्रतीक के रूप में मायावती को भेंट किए जाने लगे।

तिलक, तरजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का जो नारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बतौर गाली दिया जाता था, 'वह हाथी नहीं गणेश हैं, ब्राह्मण, विष्णु, महेश हैं के सनातनी संस्कार में बदल गया। मायावती कहने लगीं, ब्राह्मण हरिशे पर चले गए हैं, इसलिए उनकी खोई गरिमा लौटाने का काम हम करेंगे। इस गौरव के पुनर्वास के लिए मायावती ने 2017 में उत्तर-प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिषत आरक्षण के प्रस्ताव का टोटका रचकर भारत सरकार को कानून बनाने के लिए भेजा। स्वार्थपूर्ति के लिए किए जाने वाले इन आर्डबरो से पता चलता है कि हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस संविधान के प्रति निष्ठा एवं अक्षरशः पालन की शपथ लेते हैं, उसे पढ़ने-समझने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। यहीं नहीं वे जिस दल के सदस्य होते हैं और उस दल के जिस नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके गुणगान करने में थकते नहीं हैं, अमुमन उसी व्यक्तित्व की विचार-प्रक्रिया को पलती लगाते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर की चिंता ठीक थी कि मेरी चिंता इस बात के अहसास से गहरी हो जाती है कि जातिवाद और पंथवाद के रूप में मौजूद भारत की बुराईयों तथा कुरीतियों के कारण विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्व में आ सकते हैं। आज देश में करीब 1400 राजनीतिक दल हैं, जिनका प्रमुख आधार धर्म, जाति और क्षेत्रवाद है। देशभर में दलितों की आबादी 16 प्रतिशत है। पंजाब में 30 पश्चिम बंगाल में 23, उत्तर-प्रदेश में 21 और महाराष्ट्र में 10.5 फीसदी दलित आबादी है। फिर भी वे उपेक्षा के पात्र बने हैं।

■ **प्रांजल कुमार**
(वरिष्ठ पत्रकार)

राज-विचार

बांग्लादेश में अब सुरक्षित नहीं हिंदू

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नई नहीं है। इस तरह की वारदात खास मकसद के लिए की जा रही है। बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। ये हिंदू परिवार पलायन कर जाते हैं और जमीन पर कट्टरपंथी कब्जा कर लेते हैं।



बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में नरैल नामक जगह पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते बवाल हो गया और हिंदू समुदाय के घरों व मंदिर में तोड़ फोड़ की गई। इसके विरोध में देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिक हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांग की है कि क्या अवांछित हमले की स्थिति को रोकने में लापरवाही हुई और क्या पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में उचित भूमिका निभाई। यह टिप्पणी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों के बाद आई है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लाम को बदनाम करने की अफवाह है। यह सब तब हुआ जब नरैल स्थित सहपारा इलाके में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई।

बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें कोई नई नहीं हैं लेकिन इस बार चिंता की बात यह है कि हिंसा की घटनाएं अब तक एक सीमित इलाकों में होती आई थीं लेकिन अब बड़े इलाकों तक इसकी आंच पहुंच गई है। जमात-ए-इस्लामी, हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठनों का प्रभाव पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में तेजी से बढ़ा है और सेकुलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ ये संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से फैसले बदलवाने में भी सफल रहे हैं। बांग्लादेश के अलग-अलग इलाकों में प्रभाव बढ़ रहा है तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश से अब तक लगभग 2.4 करोड़ हिंदू पलायन कर चुके हैं। वर्ष 1964 से 2013 के बीच रोजाना लगभग 600 से ज्यादा हिंदू देश छोड़कर गए। यह क्रम अब भी जारी है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले 30 साल में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म होने के साथ ही हिंदू समुदाय के साथ मार-पीट शुरू हो गई थी।

बांग्लादेश के जन्म होने के बाद 1974 में जनगणना हुई थी। इसके मुताबिक देश में 1974 में 13.5 फीसदी हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2011 में देश में महज 8.5 प्रतिशत हिंदू ही रह गए थे। 2011 से 2021 तक इसमें करीब तीन फीसदी की और गिरावट आ चुकी है। आलम यह है कि हिंदुओं की संख्या साल-दर-साल घटती जा रही है। अब तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करना, हिंदुओं के घर जलाना, बच्चों और लड़कियों का अपहरण, दुष्कर्म जैसी वारदात यहां आम हो गई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। दरअसल, यहां के हिंसा के पैटर्न में देखा गया है कि बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। घर जलने से ये हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर होते हैं और जब वे पलायन कर जाते हैं तो उनकी जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं।

कथित दलित उत्थान की राजनीति

राजनेताओं और दलों ने डॉ भीमराव अंबेडकर और कथित दलित उत्थान की राजनीति को राजनीतिक हितों का साधन और साध्य बना लेने से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अतएव जो दलित एक समय मायावती की बसपा के सेवक थे, वे भाजपा के सेवादार बन गए और अब सपा के दर पर नतमस्तक हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर अति पिछड़े और दलित हैं। कमोबेश इसे ही स्वार्थपरक अवसरवादी राजनीति कहते हैं। इनके लिए अंबेडकरवादी दर्शन का आदर्श स्वाहित से आगे नहीं बढ़ पाया। मायावती ने भी अंबेडकर के जातिविहीन सामाजिक दर्शन को पूंजी व सामंती वैभव के भोग का पर्याय मान लिया। भविष्य में निर्मित होने वाली इन स्थितियों को शायद अंबेडकर ने 1956 में ही भांप लिया था। गोया, उन्होंने आगरा में भावुक होते हुए कहा था कि 'उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद दलितों में पड़े-लिखे बौद्धिक वर्ग से थी कि वे समाज को दिशा देंगे। लेकिन इस तबके ने हताशा ही किया है।' दरअसल अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य जातिविहीन समाज की स्थापना थी।

जाति टूटती तो स्वाभाविक रूप से समरसता व्याप्त होने लग जाती। लेकिन देश की राजनीति का यह दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा कि नेता सवर्ण रहे हों या अवर्ण जाति और वर्ग भेद को ही आजादी के समय से सत्तारूढ़ होने का मुख्य हथियार बनाते रहे हैं। आज मायावती को सबसे ज्यादा किसी ताल्त्विक मोह ने कमजोर किया है तो वह हैं, धन और सत्ता की लोलुपता। जबकि अंबेडकर इन आकर्षणों से सर्वथा निर्लिप्त थे। जबकि भारत ऐसा भुक्तभोगी देश रहा है, कि जब वह सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब उसे मुगलों ने लूट और फिर अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने तो सामंतों और जमींदारों को इतनी निर्ममता से लूट कि इंग्लैंड के औद्योगिक विकास की नींव ही भारत की धन-संपदा के बूते रखी गई। यहां के किसान और पिल्पकारों से खेती और वस्तु निर्माण की तकनीकें हथियाईं। भारत के भौगोलिक विस्तार की सीमाएं सिमट जाने का कारण भी पूंजी का निजीकरण और सामंतों की भोग-विलासी जीवन शैली रही है।

दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी प्रशासनिक व्यवस्था में यही दुर्गुण समाविष्ट होकर देश को दीमक की तरह चाट रहा है। दलित नेता और अधिकारी भी अधिकार संपन्न होने के बाद उन्हीं कमजोरियों की गिरफ्त में आते गए। इसीलिए अंगड़े-पिछड़ों का खेल और दल-बदल की महिमा मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कुटिल मंशा से आगे नहीं बढ़

पाई। यही वजह रही कि उत्तर-प्रदेश जैसे जटिल, धार्मिक व सामाजिक सरंचना वाले राज्य में चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती आज चुनावी सरगमियों के बीच मौन व उदासीन हैं। यह उनकी राजनीतिक निष्क्रियता की घोषणा तो है ही, कालांतर में नेपथ्य में चले जाने का संकेत भी है। वरना, एक समय ऐसा भी था, जब इस दलित नेत्री से बसपा नेतृत्व को आखिल भारतीय बना देने की उम्मीद की जा रही थी और दलितों में यह उम्मीद मायावती ने ही जगाई थी कि संगठन वह शक्ति है, जो प्रजा को राजा बना सकती है।

बहुजन समाज पार्टी का वजुद खड़ा करने से पहले कांशीराम ने लंबे समय तक डीएस-4 के माध्यम से दलित हितों के लिए संघर्ष किया था। इसी डीएस-4 का सांगठनिक ढांचा स्थापित करते समय बसपा की बुनियाद पड़ी और समूचे हिंदी क्षेत्र में बसपा के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हुई। कांशीराम के वैचारिक दर्शन में दलित और वर्चितों को करिषमाई अंदाज में लुभाने का चुबुकीय तेज था। फलस्वरूप बसपा एक मजबूत दलित संगठन के रूप में स्थापित हुई और उत्तर-प्रदेश में चार बार सरकार बनाई। अन्य प्रदेशों में बसपा के विधायक दल-बदल के खेल में भागीदार बनकर सरकार बनाने में सहायक बने। किसी दल का बहुमत न होने पर समर्थन का टेका लगाने का काम किया। केद्र में मायावती यही भूमिका अभिनीत करके राज्यसभा सांसद बनती रहीं। साधनों के अपने साध्य के लिए मायावती ने सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियरिंग) जैसे बेमेल प्रयोगों का भी सहारा लिया और इन प्रयोगों का दायित्व किसी दलित को सौंपने की बजाय, सनातनी ब्राह्मण सतीश मिश्रा के सुपुर्द किए।

मसलन सत्ता प्राप्ति के लिए जातीय समीकरण बिठाने में मायावती पीछे नहीं रहीं। अंबेडकर ने जातिविहीन समाज की पुरजोर पैरवी की थी। लेकिन कर्मचारी राजनीति के माध्यम से जातिगत संगठन बसपा की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कांशीराम ने अंबेडकर के दर्शन को दरकिनार कर कहा कि अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो। यह नारा न केवल बसपा के लिए प्रेरणास्रोत बना, बल्कि मंडलवादी मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, शरद यादव व नीतीश कुमार ने भी इसे अपना-अपना, परचम फहराने के लिए सिद्ध मंत्र मान लिया। गोया, इन नेताओं ने अंबेडकर द्वारा स्थापित जाति तोड़ो आंदोलन को जाति सुरक्षा आंदोलन में बदल दिया। इसीलिए मंडल आयोग की पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सिफारिशें मान लेने के बाद अब जातिगत

जनगणना की बात पुरजोरी से उठाई जा रही है, जिससे संख्याबल के आधार पर जातिगत आरक्षण व्यवस्था सरकारी नौकरियों के साथ विधायिका में भी की जा सके। सतीश मिश्रा के बसपा में आने के बाद सामाजिक अभियांत्रिकी का बेमेल तड़के का सिलसिला तो शुरू हुआ ही, जिन लोगों को माया मनुवादी कहकर ललकारा करती थीं, उन्हीं मनुवादियों के कर्मकांड बसपा के मंचों पर सत्ता प्राप्ति के लिए अनिवार्य अनुष्ठान बन गए। सभाओं में हवन कुंड बनाए जाने लगे और मंत्रों के उच्चारण के साथ परशुराम के सोने-चांदी के फरसे ब्राह्मणत्व के प्रतीक के रूप में मायावती को भेंट किए जाने लगे।

तिलक, तरजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का जो नारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बतौर गाली दिया जाता था, 'वह हाथी नहीं गणेश हैं, ब्राह्मण, विष्णु, महेश हैं के सनातनी संस्कार में बदल गया। मायावती कहने लगीं, ब्राह्मण हरिशे पर चले गए हैं, इसलिए उनकी खोई गरिमा लौटाने का काम हम करेंगे। इस गौरव के पुनर्वास के लिए मायावती ने 2017 में उत्तर-प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिषत आरक्षण के प्रस्ताव का टोटका रचकर भारत सरकार को कानून बनाने के लिए भेजा। स्वार्थपूर्ति के लिए किए जाने वाले इन आर्डबरो से पता चलता है कि हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस संविधान के प्रति निष्ठा एवं अक्षरशः पालन की शपथ लेते हैं, उसे पढ़ने-समझने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। यहीं नहीं वे जिस दल के सदस्य होते हैं और उस दल के जिस नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके गुणगान करने में थकते नहीं हैं, अमुमन उसी व्यक्तित्व की विचार-प्रक्रिया को पलती लगाते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर की चिंता ठीक थी कि मेरी चिंता इस बात के अहसास से गहरी हो जाती है कि जातिवाद और पंथवाद के रूप में मौजूद भारत की बुराईयों तथा कुरीतियों के कारण विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्व में आ सकते हैं। आज देश में करीब 1400 राजनीतिक दल हैं, जिनका प्रमुख आधार धर्म, जाति और क्षेत्रवाद है। देशभर में दलितों की आबादी 16 प्रतिशत है। पंजाब में 30 पश्चिम बंगाल में 23, उत्तर-प्रदेश में 21 और महाराष्ट्र में 10.5 फीसदी दलित आबादी है। फिर भी वे उपेक्षा के पात्र बने हैं।

■ **प्रांजल कुमार**
(वरिष्ठ पत्रकार)

अनियमित हो गया है। मौसम ने इतने रिकार्ड तोड़े कि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष के मौसम को 'रिकार्ड तोड़ने वाला मौसम' तक कह दिया। गौरतलब है कि फिनलैंड में जून, 1961 के बाद जुलाई, 2021 का महीना सबसे गर्म रहा। इस देश के शहर कोवोला अंजाला में 31 दिन तक लू चली। इसी साल नौ जुलाई को कैलीफोर्निया की डेथ वैली में 54.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि अपेक्षकृत टंडा समझे जाने वाले लास वेगास में पारा 47 डिग्री के पार चला गया। उधर, ब्राजील के कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं होने से सूखा आपातकाल घोषित करना पड़ा। मौसम की मनमर्जी ने चीन और बांग्लादेश में जम कर बारिश कराई।

जर्मनी में जुलाई में हुई बारिश ने सदियों के रिकार्ड तोड़ डाले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव तालस ने इस विश्वव्यापी मंजर को देख कर ही कहा था कि जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक प्रभाव से अब दुनिया का कोई देश बचा नहीं दिखता। बढ़ते वैश्विक तापमान पर 2018 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तापमान में वृद्धि के कारण पहले से ही मानव और प्राकृतिक प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस बदलाव को हिमनदों की मौजूदा स्थिति से भी आंका जा सकता है। इनके पिघलने से एक बड़ी-सी झील बन जाती है और जब वह झील फटती है तो इलाके में तबाही मच देती है। हिमनदों के पिघलने का कारण भी धरती का तापमान बढ़ना ही है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट लगातार गर्म हो रही है और इस गर्मी के कारण आसपास के हिमनद तेजी से पिघलने लगे हैं। हम इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहें या वैश्विक गर्मी या कोई और नाम दें।

सच तो यह है कि प्रकृति का अधिकाधिक दोहन करने की हमारी नीतियों और मानसिकता ने समूची मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हम सबको प्रकृति और मनुष्य की आत्मीयता के समीकरण पुनः प्रबल करने होंगे। जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर बताती है कि दुनिया ने अगर अब भी होश नहीं संभाला, तो प्रकृति कहर बरपाने पर आमदा है। भारतीय संस्कृति ने शायद इसीलिए कभी देवताओं के रूप में तो कभी परंपराओं के तौर पर प्राकृतिक शक्तियों की सामर्थ्य को नमन किया जाता रहा है। मगर आज हम प्रकृति के प्रति इस भाव को भुला चुके हैं। हमने प्रकृति के दोहन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो आज हमें विपरीत परिस्थितियों के रूप में परेशानियों को न्योता दे रहा है।

■ **विवेक सिंह**
(वरिष्ठ पत्रकार)

टिप्पटर



हिंसा को लेकर हमें कई सुराग मिले हैं और ये सभी बांग्लादेश की छवि खराब करने की कोशिश की ओर इशारा करते हैं। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं।

असदुज्जमा खान गृह मंत्री, बांग्लादेश

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मामला पड़ोसी देश के साथ उठाया गया है। वहां का दूतावास भी हिंदुओं की सुरक्षा पुष्टा कर रहा है।



एस जयशंकर, विदेश मंत्री



सत्यार्थ

स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक किस्सा है। घटना उस समय की है, जब वे स्वामी विवेकानंद नहीं, नंदनाथ के रूप में जाने जाते थे। नंदनाथ जब अपने घर से किसी धार्मिक कार्य के लिए निकलते थे तो उन्हें एक ऐसे मोहल्ले से गुजरना पड़ता था, जहां वेश्याएं रहती थीं। वेश्याएं घर के बाहर सड़क पर अपनी गतिविधियां करती थीं तो युवा नंदनाथ को बहुत शर्म आती थी। इस वजह से उन्होंने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। अब वे एक बहुत लंबे रास्ते से होकर अपनी मौजिल तक पहुंचते थे। कुछ दिनों के बाद जब वे विवेकानंद



आकर्षण की ओर मेरे मन को ले जाती है। मोहल्ले में कोई खराबी नहीं है, बात मेरे आकर्षण के भाव की है। मुझे ये आकर्षण खत्म करना चाहिए। इसके बाद मेरे

के रूप में प्रसिद्ध हो गए तो और ज्यादा प्रतिष्ठा का स्वाला था, इस वजह से वे उस मोहल्ले से गुजर नहीं सकते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके मन में विचार आया कि मैं उस मोहल्ले से क्यों नहीं गुजर सकता। अब मेरे मन में किसी भी स्त्री के लिए कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। स्वामी जी ने सोचा कि दरअसल, वेश्याओं की गतिविधियों के लिए मेरे मन में कहीं न कहीं एक आकर्षण है। मेरी वासना उस

मन में किसी के लिए कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं कहीं से भी जा सकता हूं। इस विचार के बाद से स्वामी जी ने उस मोहल्ले से गुजरना शुरू कर दिया। सारी वेश्याएं स्वामी जी को देखतीं, लेकिन स्वामी जी की उपस्थिति में वेश्याएं नतमस्तक हो जातीं और मर्यादित हो जाती थीं। धीरे-धीरे स्वामी जी को ये लगना ही बंद हो गया कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है। उनके मन से सभी तरह के भेदभाव ही खत्म हो गए। स्वामी जी हमें शिक्षा दी है कि तपस्या हमें ही करनी है, अनुशासन भी हमें ही रखना है। हमारे मन के बुरे विचार ही बाहर की बुराई में ज्यादा दिखाते हैं। अगर हम नियंत्रण में है तो बाहर की बुरी बातें भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं।

■ **राधा नावीज**

वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले में कोर्ट ने वायुसेना के 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को जारी किया समन

नई दिल्ली। देश के चर्चित 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड (वीवीआईपी) हेलीकाप्टर घोटाला मामले दिल्ली की एक कोर्ट ने वायुसेना के चार पूर्व अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने वायुसेना के अधिकारियों को 30 जुलाई को पेश होने को कहा है। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि आवश्यक प्रतिबंध इन पर लगाए गए हैं। सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड से रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 एडव्यू101 दोहरे उपयोग वाले हेलीकॉप्टर (वीवीआईपी) हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपये के अनुबंध की जांच कर रही है। फरवरी 2010 में, तत्कालीन यूपीए सरकार ने 556.262 मिलियन यूरो के 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये हेलिकॉप्टर वीवीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए खरीदे जा रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड को लाभ पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर के विनिर्देशों को मूल सौदे से बदल दिया गया था। बाद में रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि कुल सौदा 3,600 करोड़ रुपये का था। इस मामले ने तब राजनीतिक भोंड लें लिया जब कई कांग्रेस नेताओं के नाम विवाद में घसीटी गए। दुबई और भारत के कुछ बिजीलियों को भी एजेंसियों ने खरीद सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए रिश्ते तने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अपने पहले के आरोपपत्र में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान होने का आरोप लगाया था।

नीट परीक्षा: सख्ती के नाम पर छात्राओं के अंतर्वस्त्र उतरवाए, परिजनों ने केस दर्ज कराया

कोलम् । देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट (नेशनल एलेजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के दौरान केरल के कोल्लम से हेरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सख्ती के नाम पर छात्राओं के अंतर्वस्त्र (अंडरगार्मेंट्स) तक उतरवा दिए गए। इस संबंध में छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। हालांकि मोथेम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इनफ़ॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ने इस घटना से इनकार किया है। फ़िलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ़ कोटा के मोदी कॉलेज सेंटर पर चार मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें गेट पर पुलिस वालों ने रोक लिया। छात्राएं ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने समझाया और ड्रेसकोड का हवाला दिया। फिर भी वो नहीं मानी। उनके परिवार वाले भी अड गए। इसके बाद उनसे लिखित में लिया गया कि परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय होगा, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगी। परीक्षा नियमों के तहत स्टूडेंट्स फूल आस्तीन के कपड़े भी नहीं पहन कर आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसके आस्तीन को काटने बाद परीक्षा में बैठने की इजाजत होती है। कुंडल, बाली, घड़ी व अन्य सभी वस्तुओं को रख लिया जाता है। लेकिन कोटा में पहली बार देखने में आया कि दो छात्राएं अपने चेहरे को लपेट कर अंदर चली गईं। उन्हें पूरी तरह से चेक किया गया था। एएसआई गीता देवी ने बताया कि पुलिस ने गेट के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने फूल आस्तीन के कपड़े पहने हुए थे, उनकी आस्तीन काटकर अंदर भेजे गए। जिन्होंने हिजाब पहन रखा था उनको साइड में किया था। अंदर से आदेश आने के बाद युवतियों को गेट में प्रवेश दिया गया था। अंदर तलाशी लेने के लिए संस्था की अलग टीम लगी हुई थी। संस्था की टीम ने अंदर छात्राओं की तलाशी ली।

नकली लोन ऐप के जरिए भारत के लोगों को ठगते थे 3 चीनी नागरिक, जारी किया गया लुकआउट नोटिस

भुवनेश्वर । आप्रवासन ब्यूरो ने भारत में अवैध डिजिटल ऋण ऐप संचालित करने के आरोप में तीन चीनी नागरिकों के खिलाफ ‘लुकआउट’ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा से इस संबंध में अनुरोध मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया। इस महीने की शुरुआत में ऐसे ही एक आरोप में एक अन्य चीनी नागरिक के खिलाफ भी ‘लुकआउट’ नोटिस जारी किया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वे गिरोह से संबद्ध हैं और मुख्य आरोपी हैं... आरोपी व्यक्ति अवैध रूप से डिजिटल ऋण ऍप संचालित कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि देश भर में ऐप के पीड़ितों की संख्या एक लाख से अधिक है। इसमें कहा गया है कि सबूतों के अनुसार वे लोग इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में इसी तरह के घोटालों में शामिल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे जांच की जा रही है।

सिंगापुर यात्रा की अनुमति देने में विलंब के पीछे राजनीतिक कारण प्रतीत होता है: केजरीवाल

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिंगापुर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें ‘‘राजनीतिक कारणों’’ के चलते अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं कोई अपराधी नहीं हूँ।’’ केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में ‘विश्व नगर शिखर सम्मेलन’ में भाग लेने के लिए उन्हें उस देश की सरकार ने आमंत्रित किया है, जहां वह विश्व नेताओं के समक्ष ‘दिल्ली मॉडल’ पेश करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। केंद्र के उनकी यात्रा के लिए अनुमति देने में विलंब करने से नाराज केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि वह पिछले एक महीने से अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘‘ मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक मुख्यमंत्री और देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। मुझे सिंगापुर जाने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण प्रतीत होता है।’’ सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने जून में केजरीवाल को इस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। यह सम्मेलन अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले दिन आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अमतौर पर विदेश यात्राओं पर नहीं जाते, लेकिन सिंगापुर सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि यह देश के विकास से जुड़ा है।

जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नदी में फंसे दो लोगों को सेना ने बचाया

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद फंसे गए दो लोगों को सोमवार को बचाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो लोग नदी पार कर रहे थे, लेकिन अचानक बाढ़ आने से वह फंसे गए। वे नदी के बीच एक बड़ी चट्टान पर किसी तरह पहुंचे। इसके बाद, स्थानीय लोगों ने सेना को घटना की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सेना की दुर्गा बटालियन के सैनिकों ने बचाव अभियान चलाया और दोनों को बचाया।

सोमवारी पूजा के दौरान मंदिर में मची भगदड़, दो महिलाओं की हुई मौत

नई दिल्ली । सावन की पहली सोमवारी के दिन बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। घटना सीवान की है जहां के ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर में प्रवेश के दौरान हुई भगदड़ के दौरान भीड़ में दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना से थोड़ी देर के लिए मंदिर फेंपस में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। घायल दोनों महिलाओं को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है, समय से एंबुलेंस नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुष्ठ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवारी की वजह से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही थी, इसी दौरान भीड़ में तीनों महिलाएं दब गईं, जिसमें से दो महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई, वहीं दो महिलाएं भीड़ में दबने और गिरने से घायल हो गईं। सफ़िर परिसर में सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर स्थिति सामान्य किया। मुत्तका की पहचान हुसैनगंज के प्रतापपुर गांव निवासी लीलावती देवी के रूप में हुई है वहीं दूसरी मृत महिला सोहममती देवी है जो जीरादेई प्रखण्ड के पटार गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घायलों की पहचान हुसैनगंज के प्रतापपुर गांव निवासी दीनानाथ यादव देवी पत्नी आशीषा देवी और शाहबाजपुर गांव निवासी जनक देव भगत की पत्नी शिव कुमारी देवी के रूप में हुई है।

श्रीलंका की आर्थिक दुर्दशा के बाद पाक समेत दुनिया के कई देशों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)।

श्रीलंका की आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा ने दुनिया के कई देशों में बेचैनी पैदा कर दी है। कभी एशिया के खुशहाल और समृद्ध देशों में गिने जाने वाले श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के बाद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे कई मुल्कों की चिंताएं बढ़ गई हैं। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया के लगभग 13 देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आगे चलकर वे भी श्रीलंका जैसी आर्थिक अनिश्चितता के शिकार हो सकते हैं।

आज की स्थिति यह है कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खाली हो चुका है। विदेशी कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसमें खुद को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इसके चलते देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर आई है। विश्लेषक प्रो हर्ष वो पंत ने कहा कि जब कोई देश विदेशी कर्ज समथ्य पर नहीं चुका पाता तो वह डिफाल्टर हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है। यही श्रीलंका के साथ हुआ है। इसके पूर्व भी दुनिया के कई देश ऐसी तबाही देख चुके हैं। कई मुल्क इस कगार पर खड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि दुनिया में श्रीलंका ही केवल ऐसा मुल्क है, जहां आर्थिक मंदी के हालात उत्पन्न हुए हैं। इसके पूर्व दुनिया के कई मुल्?क आर्थिक मंदी के दौर से गुजर चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से अर्जेंटीना, ग्रीस, रूस, उरुग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक और इक्?वाडोर शामिल है। लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना वर्ष 2000 से 2020 के बीच दो बार इस दौर से गुजर चुका है। वर्ष 2012 में ग्रीस डिफाल्टर हो चुका है। वर्ष 1998 में रूस भी डिफाल्टर घोषित हो चुका है। इसी तरह से वर्ष 2003 में उरुग्वे और 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और वर्ष 2001 में इक्वेडोर डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। प्रो पंत ने कहा कि इस वर्ष श्रीलंका के अलावा लेबनान, रूस, सूरीनाम और जाम्बिया समय से कर्ज चुका पाने में विफल रहे हैं। बेलारूस भी जल्द ही इस कगार पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दुनिया में करीब 13 मुल्कों पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। इस क्रम में पाकिस्तान को लिया जा सकता है। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भले ही निकल गया हो लेकिन उसके आर्थिक हालात नाजुक हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आइएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान के विदेशी

मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार पर इसका जबरदस्त दबाव है। शरीफ सरकार को अब तेजी से खर्चों में कटौती करने की जरूरत है, क्योंकि वह अपने राजस्व का 40 फीसदी सिर्फ ब्याज पर खर्च कर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9।8 अरब डालर तक गिर गया है। यह पांच हफ्ते के आयात के लिए भी नाकाफी है।

प्रो पंत का कहना है कि जंग के चलते यूक्रेन की हालात जर्जर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए संकट भरा हो सकता है। प्रो पंत ने कहा कि इसी तरह से अर्जेंटीना में विदेशी भंडार की गंभीर कमी है। अर्जेंटीना के पास वर्ष 2024 तक काम करने के लिए पर्याप्त कर्ज नहीं है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया भी संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति कैस सैयद को आइएमएफ से कर्ज लेने या कम से कम उसके साथ बने रहने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि, इस चिंता में कई अफ्रीकी देश हैं, लेकिन ट्यूनीशिया सबसे अधिक जोखिम में है। ट्यूनीशिया में बजट घाटा 10 फीसदी तक पहुंच गया है। घाना की स्थिति भी नाजुक है। घाना पहले से ही राजस्व का आधा से अधिक कर्ज के ब्याज भुगतान पर खर्च कर रहा है। यहां महंगाई भी 30 फीसदी के करीब पहुंच गई है। यहीं हाल मिस्र का है। मिस्र के पास अगले पांच वर्षों में भुगतान करने के लिए सौ अरब डालर का कर्ज है।

अखिलेश पर तंज कसते हुए शिवपाल ने कहा, नेताजी का अपमान करने वाले का नहीं कर सकते समर्थन

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज मतदान संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पिछले कई दिनों से देश की राजनीतिक सरगमियां काफी गर्म थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कई बार मैंने एक करवट लेती दिखाई दे रही थी। आज एक बार फिर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। इशारों इशारों में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश ने मेरा और मुलायम सिंह यादव तक का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर अखिलेश ने उनका अपमान किया है और एक कट्टर समाई नेता जी का अपमान कभी बदरश्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा का समर्थन करने को लेकर भी शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। आज भी शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो नेता जी का अपमान करता



है, उसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। अपने बयान में शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी (मुलायम यादव) को ढूसट्ट एजेंट कहने वाले (विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा) हम उनका कभी समर्थन नहीं कर सकते। सपा के कट्टर नेता, नेताजी के सिद्धांतों का पालन करने वाले ऐसे आरोप लगाने वाले उम्मीदवार का कभी समर्थन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने कहा कि मैं यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करूंगा। देश में

रांची में केद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई

रांची (एजेंसी)।	
झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कोतवाली थाना रंजी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रतिि गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रसाद ने कहा की तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार के बयान को गायत तरीके से पेश किया। प्रसाद ने कहा कि ऐसा डॉ अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया।	एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान को आदिवासी नेता का अपमान बताया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद के चुनाव से ठीक पहले सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नयत और डॉक्टर कुमार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। ऐसा कर भाजपा ने आदिवासी समाज का अपमान किया ही साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया है। डॉ. कुमार ने अपने बयान के शुरुआत में ही राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार की प्रशंसा की थी। लेकिन उसे एडि्ट कर साजिशन यह कल्प किया गया है जो आईपीसी की धारा 153-अ 415, 469, 499, 500, 505(2) के तहत गैर कानूनी है।

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ऐसे शिक्षक ही मदरसों में दे सकेंगे तालीम

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक अब मदरसों में दीनी तालीम को कम किया जाएगा। मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक अब सिर्फ टीईटी पास शिक्षक ही मदरसों में बच्चों को तालीम दे पाएंगे। सरकार का यह फैसला मदरसा मॉडनाइजेशन स्कीम के तहत आया है। इस स्कीम के तहत से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हुए शिक्षकों की बहाली होगी। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती की नियमावली में भी संशोधन किया जा

महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर वरुण गांधी का तंज, जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।	
देश में महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इन सबके बीच भाजपा के अपने सांसद वरुण गांधी भी महंगाई के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। वरुण गांधी ने आज दूध और दही सहित कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर दी। वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैकड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकार्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। उन्होंने कहा कि जब ‘राहत’ देने का वक्त था, तब हम ‘आहत’ कर रहे हैं।	

मदरसा शिक्षक को भी डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

मदरसा शिक्षा के लिए अधिकतम उम्र तय नहीं करने जा रही योगी सरकार: अंसारी

वहीं, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों में दाखिले के लिए विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किए जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सरकार मदरसों में दाखिले की उम्र तय करने के सिलसिले में एक समिति का गठन करेगी। अंसारी ने कहा था कि मदरसों की विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु निर्धारित करने को लेकर एक समिति

गुरुग्राम-सोहना हाईवे का विधिवत शुभारंभ आज करेंगे केंद्रीय मंत्री गडकरी

गुरुग्राम । गुरुग्राम-सोहना हाईवे का विधिवत शुभारंभ मंगलवार शाम केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं, शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह, स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहने वाले हैं। पिछले सप्ताह 11 जुलाई को इसका विधिवत शुभारंभ किया जाना था, लेकिन अचानक समारोह रद्द कर दिया गया था। हाईवे आम जनता के लिए पहले ही खोला जा चुका है। इससे गुरुग्राम से सोहना तक की दूरी एक से डेढ़ घंटे की बजाय केवल 20 से 25 मिनट में लोग तय कर रहे हैं। 23 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण लगभग दो हजार करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। निर्माण बेहतर तरीके से और तेजी से हो, इस ध्यान में रखकर दो पैकेज में किया गया। पहला पैकेज राजीव चौक से लेकर बादशाहपुर तक है, जबकि दूसरा पैकेज बादशाहपुर के आगे से लेकर सोहना तक है। पहले पैकेज में सुभाष चौक के आगे से लेकर बादशाहपुर से आगे तक पांच किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक पीके कौशिक का कहना है कि समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम पांच बजे से समारोह शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी पूरे हाईवे को देखने के लिए रोड शो कर सकते हैं। यह देखकर तैयारी की जा रही है। रोड शो करने का एक उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी महिल्ला करना भी है। गांव अलीपुर के नजदीक गुरुग्राम-सोहना हाईवे से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेस का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही अलीपुर से दौसा तक का भाग चालू किया जाएगा।

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय वाराणसी में अदालत के आदेश पर हुए सर्वेक्षण में मिले ‘शिवलिंग’ की पूजा करने की अनुमति मांगने संबंधी एक नयी याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया और इस मामले को 21 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए कहा। याचिका में ‘‘शिवलिंग’’ की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग करानेका भी अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण,न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से पेश प्रतिवेदनों पर गौर किया और कहा कि याचिका को 21 जुलाई को सुनवाई के लिए ‘अंजुमन इंतैजामिया मस्जिद समिति’ की लंबित याचिका के

साथ सूचीबद्ध किया जाए।

यह समिति ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले देखती है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण को चुनौती दी गई है। कहा जाता है कि ‘शिवलिंग’ इसी परिसर में मिला है। अधिवक्ता जैन ने कहा, ‘‘ यह याचिका परिसर में मिले ‘शिवलिंग’ के ‘दर्शन और पूजा’ की अनुमति के लिए है साथ ही एएसआई को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के निर्देश देने के लिए है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मस्जिद समिति की ओर से आयोग के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। कृपया इसे भी साथ में सूचीबद्ध कर लीजिए।



आपको बता दें कि जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं। इन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसी तरह 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल के कमरों पर 12

प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। इससे पहले भी वरुण गांधी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के खिलाफ विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर मुखरता से आवाज उठा रहे हैं।

रसाई गैस की कीमतों में वृद्धि के बाद से भी पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तब वरुण गांधी ने कहा था कि अब लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। अपने ट्वीट में वरुण सांसद ने लिखा था कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। उन्होंने ने एक विडियो भी साझा किया और दावा किया कि ये उन लाजों महिलाओं का दंड है जिन्हें हमने ‘धुर्पे से आजादी’ का सपना दिखाया था। यह वही महिलाएँ हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था।



बनाई जाएगी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय लिया जाएगा और मदरसों में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार

सीबीएसई और आईसीएसई समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी दाखिले के लिए न्यूनतम

अधिकतम उम्र तय करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार

स्टार डायजेस्ट

भारतीय महिला हॉकी टीम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हुई रवाना
 बार्सिलोना । भारतीय महिला हॉकी टीम सोमवार सुबह बार्सिलोना से इंग्लैंड की राजधानी लंदन के लिए रवाना हो गई। टीम लंदन से नॉटिंघम जाएगी जहां वह 23 जुलाई को बर्मिंघम रवाना होने से पहले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अभ्यास करेगी। भारत एक जुलाई से 17 जुलाई के बीच खेले गए एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 में चीन के साथ नौवें स्थान पर रहा था। टीम की कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि वह राष्ट्रमंडल खेलों में इस फॉर्म को बदलने के लिये तत्पर हैं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश हम एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप स्पेन एवं नीदरलैंड 2022 में अपनी क्षमता के अनुसार नहीं खेल सके, लेकिन हम राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी फॉर्म को बदलने के लिये तत्पर हैं। हमारे पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलन के साथ एक बेहतरीन स्क्वाड है। हम राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़कर शुरुआत करेंगे और मुझे यकीन है कि हम प्रतियोगिता की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकेंगे।'

जब जरूरत होगी तो अपनी पूरी गति से गेंदबाजी करूंगा: हार्दिक पांड्या
 मैनचेस्टर । भारतीय आलराउंडर हार्दिक पांड्या का मानना है कि एक गेंदबाज के रूप में अंततः उन्होंने लय हासिल कर ली है और

भविष्य में जब भी जरूरत होगी तो वह अपनी पूरी गति के साथ गेंदबाजी करेंगे। फिटनेस समस्याओं के कारण नियमित रूप से गेंदबाजी नहीं कर पाने से हार्दिक ने भारतीय टीम में अपनी जगह गंवा दी थी लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के 2022 सत्र में उन्होंने जोरदार वापसी की। पंड्या ने कहा कि नियमित रूप से गेंदबाजी कर पाने से उन्हें काफी संतोष मिलता है। हार्दिक ने कहा, सबसे पहले अपनी गेंदबाजी की बात करता हूं। प्रत्येक श्रृंखला के बाद मैं चार या पांच दिन ट्रेनिंग करता हूं क्योंकि इससे मेरी फिटनेस बेहतर होती है और मैं तरोताजा रहता हूं। मैं शत प्रतिशत क्षमता के साथ खेलना पसंद करता हूं क्योंकि इससे मुझे वह सभी चीजें करने का मौका मिलता है जो मैंने आज की। आईपीएल के बाद मैंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में वापसी की। मैंने एक आखि गेंदबाजी की और फिर दो मैच में गेंदबाजी नहीं की।

इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का वनडे क्रिकेट से संन्यास

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल आखिरी मैच खेलेंगे



नई दिल्ली | एजेंसी

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे के बाद इस फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। स्टोक्स ने अब तक 104 वनडे मैच खेले हैं। 31 साल के स्टोक्स 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। यह मैच लॉर्ड्स में खेला गया था और इस इंग्लैंड ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल में उन्होंने 84 रन की पारी खेली थी। 2011 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ डक़रडेब्यू किया था। स्टोक्स ने 2919 रन बनाए हैं और 74 विकेट उनके नाम दर्ज हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीती थी सीरीज

बेन स्टोक्स ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 3-0 से वनडे सीरीज में मात दी थी। स्टोक्स ने कहा, "मैं इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच एकदिवसीय क्रिकेट में मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने इस प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह एक मेरे लिए कठिन निर्णय है। मुझे अपने साथियों के साथ खेलने को लेकर बहुत गर्व महसूस हुआ। यह निर्णय मेरे लिए बहुत कठिन था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मेरा शरीर भी अब जवाब दे रहा है। मैं खुद एक खिलाड़ी की जगह ले रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरी जगह कोई और इस फॉर्मेट में खेले और मुझसे बेहतर करे।

टेस्ट क्रिकेट लिए सबकुछ लगा दूंगा

स्टोक्स ने आगे कहा, मेरे पार अब टेस्ट क्रिकेट खेलने का समय होगा और इसके लिए मैं को सब कुछ लगा दूंगा। वहीं, टी-20 प्रारूप के लिए भी मैं पूरी तरह तैयार रहूंगा।

आईसीसी रैंकिंग : भारत ने वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मजबूत की अपनी स्थिति



दुबई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला जीत कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सोमवार को जारी नवीनतम एकदिवसीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। ऋषभ पंत की एकदिवसीय में पहली शतकीय पारी और हार्दिक पंड्या के हरफनमौला खेल से भारत ने तीसरे एकदिवसीय में इंग्लैंड को हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती।

भारत के नाम 109 रेटिंग अंक हैं जो चौथे स्थान पर काबिज पाकिस्तान (106 अंक) से तीन अंक ज्यादा है। इस

तालिका में न्यूजीलैंड 128 अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड 121 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

इस सूची में हालांकि छठे स्थान पर काबिज दक्षिण अफ्रीका के पास अपनी स्थिति को सुधारने का मौका होगा। टीम पाकिस्तान से 7 रेटिंग अंक पीछे है और इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की आगामी श्रृंखला में अगर वह सूपड़ा साफ करती है तो चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। भारतीय टीम भी अगरले सप्ताह वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है।



10 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर वर्ल्ड चैंपियन बनीं प्रेसी टूर्नामेंट में पहली बार डबल क्लीन स्वीप; विमेन के तीनों मेडल जमैकन ने जीते

यूएसए। जितनी देर में आपने इस खबर की स्लग, हेडलाइन और टैग लाइन पढ़ी है उतनी देर में जमैका की स्पिंटर शैली एना फ्रेसर प्रेसी (10.67 सेकंड) ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। वे सोमवार को फर्गटा दौड़ की वर्ल्ड चैंपियन बन गईं। यहां जमैक की रनर्स ने (गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज) तीनों मेडल जीते हैं। एक दिन पहले मंस कैटेगरी की 100 मीटर रेस में भी ऐसा ही हुआ था। रविवार को अमेरिकन रनर्स ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 100 मीटर रेस की (मंस और विमंस कैटेगरी) क्लीन स्वीप हुआ हो। इससे पहले 1991 और 1983 के सीजन की मंस कैटेगरी के धावकों ने क्लीन स्वीप किया था। दोनों ही बार अमेरिकन ने तीनों मेडल जीते थे। लेकिन उन सीजन के विमेन रेस के मेडल अलग-अलग देशों को मिले थे। विमंस में पहली बार किसी देश ने क्लीन स्वीप किया है।

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, जेसन होल्डर की वापसी

पोर्ट ऑफ स्पेन। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 22 जुलाई से वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेगी। टीम इंडिया पहले ही वनडे और टी-20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर चुकी है। सोमवार को वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम में पूर्व कप्तान जेसन होल्डर की वापसी हुई है। होल्डर बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी-20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। क्रिकेट वेस्टइंडीज के चयन पैनल ने उन्हें भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में वापस बुलाने का फैसला किया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक बयान में मुख्य चयनकर्ता डेसमंड हेन्स की ओर से कहा गया है कि जेसन दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में से एक हैं। उन्हें टीम में वापस शामिल करने पर हमें खुशी है। वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ तीन वनडे मैच 22, 24 और 27 जुलाई को वर्वीस पार्क ओवल में खेलना है। उसके बाद 5 टी-20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है। सीरीज के आखिरी दो मैच अमेरिका में खेले जाने हैं। वेस्टइंडीज टीम इस प्रकार है: निकोलस पून (कप्तान), शाई होप, शेमार ब्रूक्स, कोसी कार्टी, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, काइल मायर्स, गुडार्थ मोती, कीमो पॉल, रोबर्मेन पॉवेल और जेडन सील्स।

भारतीय वनडे टीम- शिखर धवन (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), ऋतुगुण गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सुर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजु समसन (विकेटकीपर), शार्दूल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अश्विनी सिंह।

व्यापार स्टार

सामान को रिटर्न करने का ट्रेंड बढ़ा: ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा 50 फीसदी कपड़े वापस करने का क्रेज, कोविड काल में और बढ़ा

लंदन | एजेंसी

ग्राहकों के ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदे सामान को वापस करने के बढ़ते ट्रेंड को निराश करने के लिए रिटेलर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आजमा रहे हैं। रिटर्न की बढ़ती लागत ने उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे ग्राहकों की ऑनलाइन खरीदी में और ज्यादा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे रहे हैं जिससे वे आयटम का बेहतर चुनाव कर सकें। जैसे बाॅडी स्कैनिंग मशीन, अवतार, वीडियो, फोटो के जरिये आयटम की बेहतर जानकारी देना। आयटम ऑनलाइन खरीदे गए सामान को लौटाने का ट्रेंड वैैसे तो सभी तरह के आयटमम्स में है लेकिन कपड़ों में यह 50% तक है। कोविड काल में आयटम ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ही वापसी का ट्रेंड बढ़ा है। जिगजैग ग्लोबल के रिटर्न्स स्पेशलिस्ट



अल गैरी का कहना है कि अब 40% से ज्यादा शॉपर्स आयटम अर्डर देते समय कम से कम एक आयटम वापस करने की सोच रखते हैं जो कि कोविड के पहले 30% था। उनका कहना है कि लोग लाॅकडाउन में आयटम ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर आयटम और सहज हुए हैं।

अल गैरी का कहना है कि अब 40% से ज्यादा शॉपर्स आयटम अर्डर देते समय कम से कम एक आयटम वापस करने की सोच रखते हैं जो कि कोविड के पहले 30% था। उनका कहना है कि लोग लाॅकडाउन में आयटम ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर आयटम और सहज हुए हैं।

वापस के ट्रेंड का 2025 तक 9 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान

ग्लोबल डेटा के एनालिस्ट के मुताबिक 2020 में ब्रिटेन में 59,618.51 करोड़ रुपए कीमत के प्रोडक्ट्स ग्राहकों ने वापस कर दिए। 2025 तक इसमें 9% की बढ़ोतरी का अनुमान है। कोविड लाॅकडाउन खत्म होने के बाद खासकर परिधानों में नए ट्रेंड आयटम आने के बाद ग्राहकों ने एक किस्म के दो प्रोडक्ट आयटम ऑर्डर करने आयटम और आयटम अजमाने के बाद कोई एक वापस करना शुरू कर दिया। ग्लोबल डेटा के पैट्रिक आयटम ओ ब्राएन का कहना है कि दुनिया में महंगाई बढ़ने के कारण ग्राहक अपनी खरीद को लेकर आयटम और ज्यादा चूज़ी हो गए हैं।

रिटर्न से बढ़ रहा कचरा, 5% ड्रेस दोबारा बेचे जाने की हालत में नहीं होते रिटर्न सामान में से 50 से 80% तक ही तुरंत बेचने लायक होता है। रिटर्न किए गए 5% ड्रेस दोबारा बेचे जाने की हालत में नहीं होते। बाकी कोरी-प्रोसेस के लिए भेजा जाता है आयटम और वहां से चेरिटी आयटम और थोक आयटम ऑनलाइन विक्रेता या शोरूम से बेचने के लिए भेजा जाता है। रिटर्न होने वाला बिजली का करीब 15% सामान बेकार हो जाता है जिसे डिस्पोज करना पड़ता है। ब्राएन का कहना है कि व्यवहार में बदलाव जरूरी है क्योंकि रिटर्न से बहुत कचरा पैदा हो रहा है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है।

तेल 100 डॉलर के नीचे, बाकी इंपोर्ट भी होगा सस्ता

»आम आदमी को जल्दी ही महंगाई से निजात मिल सकती है
 »कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है
 »कमोडिटीज की कीमतों में भी हाल में काफी गिरावट आई है
 »आरबीआई के मुताबिक महंगाई से जल्द राहत मिल सकती है

नई दिल्ली | एजेंसी

महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में भी गिरावट आई है। इससे आने वाले दिनों में इंपोर्ट सस्ता होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो इससे देश में महंगाई से निजात मिल सकती है। आरबीआई का भी कहना है कि अगर कमोडिटीज की कीमत में नरमी बनी रहती है और सप्लाई-चेन का दबाव कम होता है तो आने वाले दिनों में महंगाई से पीछा छूट सकता है। अभी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में महंगाई चरम पर है। भारत में भी महंगाई इस साल जनवरी से ही आरबीआई की तय सीमा से ऊपर बनी हुई है। महंगाई से निपटने के लिए आरबीआई ने हाल में दो



किस्तों में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। अगर महंगाई में कमी आती है तो आने वाले दिनों में इंपएमआई यानी किस्त में भी राहत मिल सकती है।

आरबीआई ने अपनी ताजा स्टेट आफ द इकानामी में कहा कि है कि

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि महंगाई अपने चरम स्तर से थोड़ा नीचे आई है। हालांकि यह अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि हाल के दिनों में कमोडिटीज की कीमत में गिरावट आई है। अगर यह स्थिति आगे भी जारी रहती है और इसके साथ ही सप्लाई-चेन की समस्याएं कम होती हैं तो महंगाई का चरम दौर पीछे छूट जाएगा। इससे भारतीय इकॉनमी वैश्विक महंगाई के मकड़जाल में फंसेने से बच सकती है।

नई दिल्ली।

आज सोना-चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक, सरार्फा बाजार में सोना 226 रुपए महंगा होकर 50,629 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो ये 807 रुपए महंगी होकर 55,574 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1,719.01 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 21.47 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है।



कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत

कैरेट	भाव (रुपए/10 ग्राम)
24	50,629
23	50,426
22	46,376
18	37,972

पहले ही दिन बाजार में आई बहार सेंसेक्स 760 अंक उछला



मुंबई | एजेंसी

शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी आज एक फीसदी से अधिक मजबूत हुए। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच आईटी, तेल और गैस तथा बैंकिंग शेयरों में लिवाली से घरेलू बाजार में तेजी आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 760.37 अंक यानी 1.41 फीसदी की बढ़त के साथ 54,521.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 795.88 अंक तक चढ़ गया था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 229.30 अंक यानी 1.43 फीसदी मजबूत होकर 16,200 अंक के पार 16,278.50 अंक पर बंद हुआ।

इन शेयरों में आया उछाल

सेंसेक्स के शेयरों में इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में डॉ. रेड्डीज लैब, एचडीएफसी बैंक, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिट्रीवर और एचडीएफसी शामिल हैं। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जारी है। उन्होंने शुक्रवार को 1,649.36 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख से आई तेजी

आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के बुनियादी शोध प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा, एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू बाजार बढ़त के साथ खुला। दोपहर के कारोबार में आईटी, प्रौद्योगिकी और पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में और मजबूती आई। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से भी बाजार को समर्थन मिला।

पाक कबायली परिषद ‘जिरगा’ ने महिलाओं के पर्यटन- मनोरंजन स्थलों पर जाने से लगाई पाबंदी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान महिलाओं की आजादी को लेकर संकीर्ण सोच रखता है अब यहां एक कबायली परिषद ‘जिरगा’ ने महिलाओं के पर्यटन और मनोरंजन के वास्ते सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक लगा दी है और इसे ‘अनैतिक’ और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। खबर के अनुसार बाजोर कबायली जिले में अति-रूढ़िवादी सालारजई तहसील की जिरगा (कबायली परिषद) ने शनिवार को घोषणा की कि यदि सरकार ने रविवार तक इस निर्णय को लागू नहीं किया तो जिरगा सदस्य इसे लागू करने के लिए इसे अपने हाथ में लेंगे। जिरगा का आयोजन जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जैयुआई-एफ) की स्थानीय इकाई द्वारा किया गया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य घटकों में से एक है। यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब विश्व आर्थिक मंच ने कुछ ही दिन पहले जारी अपनी वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया के साथ-साथ क्षेत्र में लैंगिक समानता के मामले में दूसरे सबसे खराब देश का स्थान दिया था। इस बैठक में सालारजई तहसील के विभिन्न कबायलियों के वरिष्ठों के अलावा, क्षेत्र के कई जैयुआई-एफ नेताओं और धार्मिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन जैयुआई-एफ जिला नेतृत्व द्वारा किया गया था। जैयुआई-एफ के जिला प्रमुख मौलाना अब्दुर रशीद और अन्य वक्ताओं ने शनिवार को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिरगा का उद्देश्य ईद के दौरान उभरे कई मुद्दों पर चर्चा करना और उन्हें शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना था। जिरगा में शामिल वक्ताओं ने कहा कि यह गौर किया गया है कि पुरुषों के अलावा, कई स्थानीय महिलाएं अपने पति या अन्य रिश्तेदारों के साथ अथवा अकेले ही ईद की छुट्टियों के दौरान विभिन्न पर्यटन एवं फिजिकि स्थलों का दौरा करती हैं। जिरगा में दावा किया गया कि यह ‘इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित’ स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ है। वक्ताओं ने कहा कि पर्यटन और मनोरंजन के लिए उक्त स्थानों पर महिलाओं का जाना ‘पूरी तरह से अनैतिक और अस्वीकार्य’ है। उन्होंने दावा किया कि इस्लाम और स्थानीय परंपराओं, दोनों में इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।

UK PM: कैबिनेट में बोरिस जॉनसन को कोई नहीं चाहता

लंदन । ब्रिटेन में सियासी घमासान के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर कई बार खतरा मंडराया लेकिन इस बार वह अपनी सत्ता को वाह कर भी नहीं बचा पाए। हाल इतना बुरा है कि अब किसी भी दावेदार ने बोरिस जॉनसन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का वादा नहीं किया है। टोरी लीडरश्रीप के अंदर टॉम तुर्गेदहट, पेनी मोडीट, ऋषि सुनक, लिज ट्रस और केमी बडेनोच से दो बार सवाल के जवाब में हाथ उठाने का अनुरोध किया गया था। जिसमें पूछा गया कि क्या बोरिस जॉनसन को सेवा जारी रखने की अनुमति देने के इच्छुक होंगे या नहीं। हालाँकि उनके पास हाथ उठाने के बहुत अवसर थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि कोई भी बोरिस जॉनसन को अपने कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहता है।

श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश में आपातकाल की घोषणा

कोलंबो। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले देश में आपातकाल की घोषणा की। देश में राजनीतिक संकट और अराजकता के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से यह पद रिक्त है। देश में आपातकाल की घोषणा वाला 17 जुलाई की तारीख वाला सरकारी आदेश सोमवार सुबह जारी किया गया। देश की 225 सदस्यीय संसद में दो दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है। गौरतलब है कि जन सुरक्षा अध्यादेश के भाग दो के तहत राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्तियां हैं। अध्यादेश के इस भाग में लिखा है, “अगर राष्ट्रपति का विचार है कि पुलिस हालात को संभाल पाने में विफल है तो वह एक आदेश जारी करके सशस्त्र बलों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह सकते हैं।” इसका तात्पर्य है कि सुरक्षा बलों को छापे मारने, गिरफ्तार करने, जल करने, हथियार और विस्फोटकों को हटाने या किसी भी व्यक्ति के आवास में घुसने और तलाशी देने का अधिकार है। राजपक्षे फिलहाल सिंगपुर में हैं।

अमेरिका में फिर दिनदहाड़े शूटआउट! इंडियाना स्टेट मॉल में घुसकर शख्स ने की गोलीबारी, 3 निर्दोषों ने तोड़ा दम

वाशिंगटन । अमेरिका में वीकेंड पर लोग अपने परिवार के साथ एंजोय करने के लिए मॉल आये थे तभी एक अज्ञात शख्स ने अवाक लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियाना स्टेट मॉल के एक फूड कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। अमेरिकी पुलिस ने कहा कि बंदूकधारी को एक सशस्त्र नागरिक ने मार गिराया। घटना ग्रीनवुड पार्क मॉल की है। ग्रीनवुड पुलिस विभाग के चीफ ज़िम इसन ने बताया कि दोनों घायलों को पास ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मेयर मार्क मायर्स ने कहा ग्रीनवुड पुलिस विभाग द्रुतय के नियंत्रण में है। मैं कमांड पोस्ट के सीधे संपर्क में हूँ, और आगे कोई खतरा नहीं है। बंदूकधारी, एक वयस्क पुरुष, को एक सशस्त्र नागरिक ने गोली मार दी थी। हालांकि, शूटिंग के पीछे किसी भेकसद या मंशा का अभी तक अधिकारियों को पता नहीं चला है। चीफ ज़िम इसन ने एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि स्थानीय आपातकालीन कॉल सेंटर को शाम 6 बजे GMT के आसपास फूड कोर्ट में शूटिंग के बारे में कॉल आने लगीं। फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि पुलिस ने कहा कि शूटर के पास एक लंबी राइफल और गोला-बारुद की कई पत्रिकाएं थीं।

अमेरिकी अरबपति मार्क क्यूबन अब तक नहीं भूले कि बिल गेट्स ने चुरा ली थीं उनकी गर्लफ्रेंड्स

कैलिफोर्निया। अमेरिकी अरबपति मार्क क्यूबन ने बताया है युवावस्था में मशहूर कारोबारी बिल गेट्स ने उनकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करके उन्हें, उनसे दूर कर दिया था। 63 साल के मार्क इस समय दुनिया के जाने-पहचाने चेहरे हैं। वे शार्क टैंक के इन्वेस्टर हैं और इस शो के साथ वह सुपरहिट हो चुके हैं। मार्क ने जो किस्सा सुनाया है वह सन् 1980 के दशक का है। उस दौर में लास वेगास में कुछ ऐसा हुआ, जिसे वह आज तक भुला नहीं पाए। मार्क ने बताया सन 1986 में कंप्यूटर ट्रेड शो कॉम्पेक्स के दौरान यह घटना हुई थी। उस समय बिल की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पहली बार सार्वजनिक हुई थी। मार्क ने कहा इसके बाद ही बिल गेट्स ‘किंग ऑफ टैक’ बन गए। मार्क क्यूबन के मुताबिक उस समय उनकी उम्र करीब 26-27 साल रही होगी। उन्होंने बताया एक वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शराब खरीद रहे थे और तभी गर्लफ्रेंड्स ने कहा कि उन्हें वीशरूम जाना है। वे वीशरूम गईं लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं। उनके अचानक इस तरह से गायब होने से वह परेशान हो गए। इसी समय किसी ने उन्हें बताया कि बिल गेट्स उन लड़कियों के साथ वहां से बाहर निकल गए हैं। व ग्युबन ने शिकायती तल्हजे में कहा कि बिल गेट्स ने मेरी गर्लफ्रेंड्स चुरा ली थीं। मार्क व ग्युबन के मुताबिक इस घटना के बाद उनकी और बिल गेट्स की एक ही बार मुलाकात हुई है और इस मीटिंग ने गेट्स को काफी नाराज कर दिया था। उन्होंने बताया कि एक कॉन्फेंस में दोनों का आमना-सामना हुआ और यहा पर दोनों की स्त्रीय होनी थी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने बिल गेट्स पर एक ऐसा जोक मारा जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। इसके बाद से आज तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तक गेट्स की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है।

शराब के सेवन से युवाओं में भी बढ़ जाता है स्वास्थ्य का जोखिम, अध्ययन में सामने आई जानकारी

वाशिंगटन । युवाओं को ज्यादा उम्र वाले लोगों की तुलना में शराब के सेवन से अधिक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रमुख शोध पत्रिका में शुक्रवार को प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में यह बात कही गई है। भौगोलिक क्षेत्र, आयु, लिंग और वर्ष के आधार पर शराब से जुड़े जोखिम के बारे में यह पहला अध्ययन है। अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में शराब की खपत की सिफारिशें उम्र और स्थान पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें सबसे सख्त दिशानिर्देश 15-39 साल के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए लक्षित हों। अध्ययन में कहा गया है कि इस उम्र समूह में शराब के सेवन से स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं हो तो 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को कम मात्रा में शराब के सेवन से कुछ लाभ मिल सकता है।



दक्षिण पश्चिम फ्रांस के जंगलों में लगी आग से निकलता हुआ धूआं।

नाटो में योगदान के लिए कितनी तैयार है जर्मनी की सेना?

कीव (एजेंसी)।

नाटो खुद को फिर से संगठित कर रहा है और जर्मनी पूर्वी हिस्से में नाटो के रैपिड रिसॉन्स फोर्स के लिए अपने 15 हजार सैनिक भेज रहा है। हालांकि इस वजह से जर्मन सेना के सामने भी कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। नाटो रिसॉन्स फोर्स यानी एनआरएफ इसकी ‘फायरवॉल’ जैसी होती हैं। इसकी बहुराष्ट्रीय युद्धक इकाइयों को स्टैंडबाई यानी आपातस्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आपातस्थिति में इसकी पहली यूनिट जिन्हें एनआरएफ कहा जाता है, वो संकटग्रस्त इलाकों में 48 घंटे के भीतर पहुंचकर जमीन, हवा अथवा समुद्र में अपने मिशन में लग जाती हैं।

एनआरएफ से उम्मीद है कि वो जल्दी ही और प्रभावी तरीके से कार्यवाई करेगा। पिछले हफ्ते मैड्रिड में हुए नाटो सम्मेलन में गठबंधन ने अपनी पूर्वी सीमाओं को और मजबूत करने के लिए रिसॉन्स फोर्स की संख्या को 40 हजार से बढ़ाकर तीन लाख करने का फैसला किया है।

जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लैंब्रेथ ने घोषणा की है कि जर्मनी अपने उन 3-5 हजार सैनिकों को यहां भेजेगा जो अभी तक लिथुआनिया में तैनात हैं। अब तक पूर्वी इलाके में जर्मनी के करीब एक हजार सैनिक ही तैनात

हैं। इसके अलावा जर्मनी 65 एअरक्राफ्ट और 20 पानी के जहाज के साथ ही विशेष कमांडो दस्ते भी भेज रहा है।

नाटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग चाहते हैं कि यहां अगले साल तक नई रैपिड रिएक्शन बल काम करना शुरू कर दे और उनकी इसी इच्छ है जर्मन सशस्त्र बल यानी बुंडेसवेयर पर दबाव बढ़ा दिया है।

बुंडेसवेयर की परेशानी

ब्रसेल्स का नाटो मुख्यालय अब और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा जागृत हो गया है। वहीं गठबंधन, जिसे कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने «ब्रेन डेड कहा था। हालांकि जर्मनी की प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा समझदारी वाली है। बुंडेसवेयर की मौजूदा स्थिति इस बात पर संदेह पैदा करती है कि क्या वह नाटो की नई जिम्मेदारी को निभा पाएगी,, क्योंकि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से इसे काफी घटा दिया गया है।

जर्मनी की सेना में कितनी बुराइयां भरी हैं इसे अप्रैल में जर्मन संसद में एक बहस के दौरान लैंब्रेथ के भाषण में देखा जा सकता है। सोशल डेमोक्रेट नेता का कहना था कि कागज पर हमारे पास 350 प्यूमा इफैंट्री फाइट वेहिकल हैं जबकि उनमें से सिर्फ 150 गाड़ियां ही काम

लायक हैं।

यही स्थिति टाइगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की है। 51 में से सिर्फ नौ ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षात्मक वेस्ट्स, बैकपैक्स और रात में देखने में मदद करने वाले उपकरणों की भी कमी है। यहां तक कि पूर्वी हिस्से में तैनात नाटो के सैनिकों के लिए गर्म अंडरवेयर की भी कमी है। बुंडेस्टाग डिफेंस कमिश्नर और चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स की सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सदस्य एफा होगल को लगता है कि एनआरएफ को बढ़ावा देने से बुंडेसवेयर पर बोझ बढ़ेगा। अखबार ऑग्सबुर्गर अल्तेमोनाझे से बातचीत में वो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जर्मनी से अपेक्षाएं और बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि बुंडेसवेयर के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उससे सैनिक, सामान, उपकरण और आधारभूत ढांचे में मदद की उम्मीद की जाएगी।

बड़ी चुनौतियां

जर्मन सशस्त्र बल एसोसिएशन यानी बुंडेसवेयर फबैंड सेना के 183,000 सैनिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष आंद्रे नुसनर कहते हैं कि ‘सेना इस मुद्दे पर बड़ी चुनौती का सामना कर रही है जो कि बुंडेसवेयर को इससे पहले कभी नहीं करना पड़ा।’

इमरान खान ने पंजाब उपचुनाव में किया क्लीन स्वीप, पीएम शरीफ को करारा झटका



लाहौर। (एजेंसी)।

अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब के महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनावों में ‘क्लीन स्वीप’ किया, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बड़ा झटका लगाहै। चुनाव परिणाम के बाद शहबाज के मुख्यमंत्री बेटे हमजा शहबाज अपना पद गंवाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री के लिए चुनाव 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हांगा और पीटीआई-पीएमएलक्यू के

संयुक्त उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत पंजाब के नए मुख्यमंत्री होने की संभावना है। अब तक के अनाधिकारिक नतीजों के मुताबिक पीटीआई ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को सिर्फ तीन सीटों पर जीत मिली है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। शरीफ परिवार की सत्तारूढ़ पीएमएल-एन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और यहां तक कि उपचुनावों में ‘भूखलाने की जीत’ के लिए पीटीआई अध्यक्ष खान को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मलिक अहमद खान ने कहा कि हम लोगों के जनாदेश का सम्मान करते हैं। अब हम पीटीआई-पीएमएलक्यू से पंजाब में सरकार बनाने को कहते हैं।

लाहौर (एजेंसी)।

भारत की एक 90 वर्षीय महिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में अपने पुरतैनी घर का दौरा करने के लिए शनिवार को जब वाषा-अटारी सीमा के रास्ते लाहौर में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रीना छिब्बर वर्मा लाहौर से सीधे रावलपिंडी रवाना हुईं, जहां वह अपने पुरतैनी आवास ‘प्रेम निवास’ और स्कूल का दौरा करने के साथ ही बचपन के दोस्तों से मिलेंगी।

सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में वर्मा ने बताया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब उनका परिवार रावलपिंडी के देवी कॉलेज रोड पर रहता था। उन्होंने कहा, ‘मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी। मेरे चार भाई-बहनों ने भी उसी स्कूल से शिक्षा हासिल की थी। वहीं, मेरे एक भाई और एक बहन ने मॉडर्न स्कूल के पास स्थित गॉर्डन कॉलेज से पढ़ाई की थी।’ वर्मा ने कहा, ‘मेरे बड़े



भाई-बहनों के कई मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे, जो अक्सर हमारे घर आते थे। मेरे पिता खुले विचारों वाले थे और उन्हें लड़कें-लड़कियों के मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी।उन्होंने कहा, ‘बंटवारे से पहले हिंदू-मुस्लिम जैसा कोई मुद्दा नहीं था। यह सब विभाजन के बाद हुआ। भारत का बंटवारा यकीनन गलत था, लेकिन चूंकि यह हो चुका है, इसलिए दोनों देशों की सरकारों को वीजा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।’ भारत स्थित पाकिस्तानी

सिंगापुर पहुंचने पर गोटबाया राजपक्षे का विरोध, कुछ लोगों ने किया मौन प्रदर्शन

सिंगापुर । श्रीलंका राष्ट्रपति पद से बेदखल किए गए गोटबाया राजपक्षे के पिछले गुरुवार को यहां पहुंचने पर सिंगापु्र के कुछ लोगों ने मौन प्रदर्शन किया। गोटबाया के गुरुवार को सिंगापु्र पहुंचने के तुरंत बाद पुलिस ने संभावित प्रदर्शनकारियों को कानून तोड़ने के परिणामों को लेकर आगाह किया। पुलिस ने कहा कि जनता, सिंगापुर के नागरिक, निवासी, वक्त पास धारक और सामाजिक आगंतुक समान रूप से स्थानीय कानूनों का पालन करें। खबरों में पुलिस का हवाला देते हुए कहा, ‘सार्वजनिक सभा, जो अवैध है उसमें भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’ गुरुवार को बनाई गई चेंज डॉट ओआरजी नामक याचिका में व्यवसायी रेमंड एनजी ने लिखा कि ‘सिंगापुर गणराज्य के प्रति निष्छ’ के चलते उन्होंने, धन शोधन के आरोप में राजपक्षे के खिलाफ सिंगापु्र में एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है। शनिवार तक, 2,000 से अधिक लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि इनमें से कितने विशिष्ट थे या सिंगापु्र से थे। सिंगापु्र के फैसले पर नाराजगी जाहिर करने के लिए कई श्रीलंकाई लोग टिक्टर पर सिंगापु्र सरकार के टिव्टर अकाउंट को टैग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि सिंगापु्र को राजपक्षे को प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब वह गुरुवार को गंगी हवाई अड्डे पर पहुंचे, तब भी वे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। राजपक्षे ने औपचारिक रूप से शुक्रवार को इस्तीफा दिया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शीर्ष सुरक्षा प्रमुख और महाभियोजक को पद से हटाया



विनितिस्या (यूक्रेन)। (एजेंसी)।

रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज किये जाने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सुरक्षा प्रमुख और महाभियोजक को रिविार को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति ने दोनों को बर्खास्त करने के पीछे देशद्रोह और विभाग के लोगों तथा कानून प्रवर्तन अन्‍य एजेंसियों के लोगों के साथ सांघाट करने के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा, “ अभियोजन कार्यालय के ओर एसबीयू (राज्य सुरक्षा सेवा) के 60 से अधिक कर्मचारी कब्जे वाले क्षेत्र में हैं और उन्होंने देश के खिलाफ काम किया।”

जेलेंस्की ने रात के वक्त देश के नाम संबोधन में जारी एक वीडियो में कहा, “ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा

प्रतिष्ठानों के खिलाफ इस प्रकार के अपराध तथा यूक्रेनी सुरक्षा बलों और रूसी विशेष सेवा के बीच संबंध बेहद गंभीर सवाल पैदा करते हैं।” उन्होंने एसबीयू के प्रमुख इवान बकानोव को पद से बर्खास्त कर दिया। बकानोव जेलेंस्की के बचपन के मित्र हैं और पूर्व कारोबारी साझेदार भी। युद्ध शुरू होने के बाद से ही बकानोव के खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे थे। पिछले महीने से अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थींकि जेलेंस्की उनका विकल्प तलाश रहे हैं। राष्ट्रपति ने इरयाना वेनेदिकोवोवा को भी महाभियोजक पद से बर्खास्त कर दिया है। जगह उनकी सहायक ओलेक्सीय साइमोनेन्को को महाभियोजक बनाया गया है।

रावलपिंडी में पुश्तैनी घर का दौरा करेगी 90 वर्षीय भारतीय महिला

उच्चायोग ने सद्भावना के तौर पर वर्मा को तीन महीने का वीजा जारी किया है, जो 1947 में विभाजन के समय महज 15 साल की थीं, जब उनका परिवार भारत आ गया था। वर्मा ने सबसे पहले 1965 में पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन युद्ध के महेनजर दोनों देशों के बीच भारी तनाव के कारण यह ठुकरा दिया गया था। वर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले साल सोशल मीडिया पर अपने पुरतैनी घर का दौरा करने की

प्रोफाइल का विवरण दिया गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रभावित होने वाले लगभग सभी रोगी पुरुष हैं, जिनकी औसत आयु 37 वर्ष है, जिनमें से अधिकतर पुरुष पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं।

अधिकांश मंकीपॉक्स संक्रमण पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में देखे गए हैं। ट्रेड्सो एडनॉम ने कहा कि डब्ल्यूएचओ नागरिक समाज और एलजीबीटीक्यू समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वायरस को अब एक स्ट्रिप्मा के रूप में देखा जा रहा है। जिसे रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ कार्य कर रहा है। एक हफ्ते पहले, डब्ल्यूएचओ ने मंकीपॉक्स के प्रसार पर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें अब तक के प्रकोप से प्रभावित लोगों की विशिष्ट

जिनेवा (एजेंसी)।

क्या मंकीपॉक्स का प्रकोप वैश्विक आपातकाल की श्रेणी में आता है या नहीं। आगामी 21 जुलाई को होने वाली विशेषज्ञ मंकीपॉक्स समिति की बैठक में इसका फैसला होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मंकीपॉक्स पर डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन समिति की यह दूसरी बैठक होगी जिसमें 63 देशों में अब तक आये 9,200 मामलों की जानकारी दी जाएगी। मई की शुरुआत से पश्चिम और मध्य

अफ्रीकी देशों के बाहर मंकीपॉक्स के संक्रमण में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां यह बीमारी बार-बार सामने आती रहती है।इससे पहले 23 जून को हुई मीटिंग में भी डब्ल्यूएचओ द्वारा इस बात पर चर्चा मंकीपॉक्स समिति की बैठक में इसका हेल्थ इमर्जेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की श्रेणी में आती है। हालांकि, अधिकतर सदस्यों ने डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयस के प्रभाव करने के बारे में स्थिति इतनी भी बेकाबू नहीं हुई है। लेकिन अब बढ़ते हुए मामलों के बीच एक बार

फिर डब्ल्यूएचओ उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि आपातकालीन समिति डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक को अपने विचार देगी कि क्या यह बीमारी पीएचडिआईसी की श्रेणी में आती है। यदि ऐसा है, तो कमेटी बीमारी के प्रसार को बेहतर ढंग से रोकने और कम करने और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का प्रबंधन करने के बारे में अस्थायी सिफारिशों का प्रस्ताव करेगी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अब तक

अधिकांश मंकीपॉक्स संक्रमण पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में देखे गए हैं। ट्रेड्सो एडनॉम ने कहा कि डब्ल्यूएचओ नागरिक समाज और एलजीबीटीक्यू समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वायरस को अब एक स्ट्रिप्मा के रूप में देखा जा रहा है। जिसे रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ कार्य कर रहा है। एक हफ्ते पहले, डब्ल्यूएचओ ने मंकीपॉक्स के प्रसार पर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसमें अब तक के प्रकोप से प्रभावित लोगों की विशिष्ट

